

डजिटल इंडिया पहल के नौ वर्ष

प्रलम्ब के लयि:

डजिटल इंडिया पहल, जीवन स्तर, पारदर्शता को बढ़ावा देना, [ई-गवर्नेंस](#), [आर्थिक विकास](#), [कॉमन सर्विस सेंटर](#), [IT कौशल](#), [डजिटल साक्षरता](#), [IT अधिनियम 2000](#),

मेन्स के लयि:

डजिटल इंडिया पहल की चुनौतियाँ, पहल ।

[स्रोत: पी. आई. बी.](#)

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने [डजिटल इंडिया पहल](#) के 9 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने की सराहना की है । प्रधानमंत्री ने कहा कि डजिटल इंडिया एक सशक्त भारत का प्रतीक है जिससे लोगों का 'जीवनयापन और ज़्यादा आसान' होता जा रहा है एवं पारदर्शता भी बढ़ रही है ।

डजिटल इंडिया पहल क्या है?

परिचय

- डजिटल इंडिया 1 जुलाई, 2015 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था ।
- यह कार्यक्रम 1990 के दशक के मध्य में शुरू हुए [ई-गवर्नेंस](#) प्रयासों पर आधारित है, लेकिन इसमें सामंजस्य और अंतरक्रियाशीलता का अभाव था ।

उद्देश्य:

- डजिटल विभाजन को कम करना:** यह पहल तकनीक-प्रेमी व्यक्तियों और सीमिति डजिटल पहुँच वाले लोगों के बीच असमानता को कम करने के लिये काम करती है ।
- डजिटल भागीदारी को बढ़ावा देना:** यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सरकारी सेवाओं जैसे क्षेत्रों को शामिल करते हुए सभी नागरिकों के लिये [डजिटल प्रौद्योगिकी](#) लाभों तक समान पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास करता है ।
- आर्थिक विकास को बढ़ावा देना:** तकनीकी प्रगति और नवीन समाधानों का उपयोग करके, डजिटल इंडिया का उद्देश्य पूरे देश में [आर्थिक विकास](#) को बढ़ावा देना है ।
- जीवन स्तर को उन्नत करना:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रौद्योगिकी के रणनीतिक अनुप्रयोग के माध्यम से नागरिकों के जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाना है ।

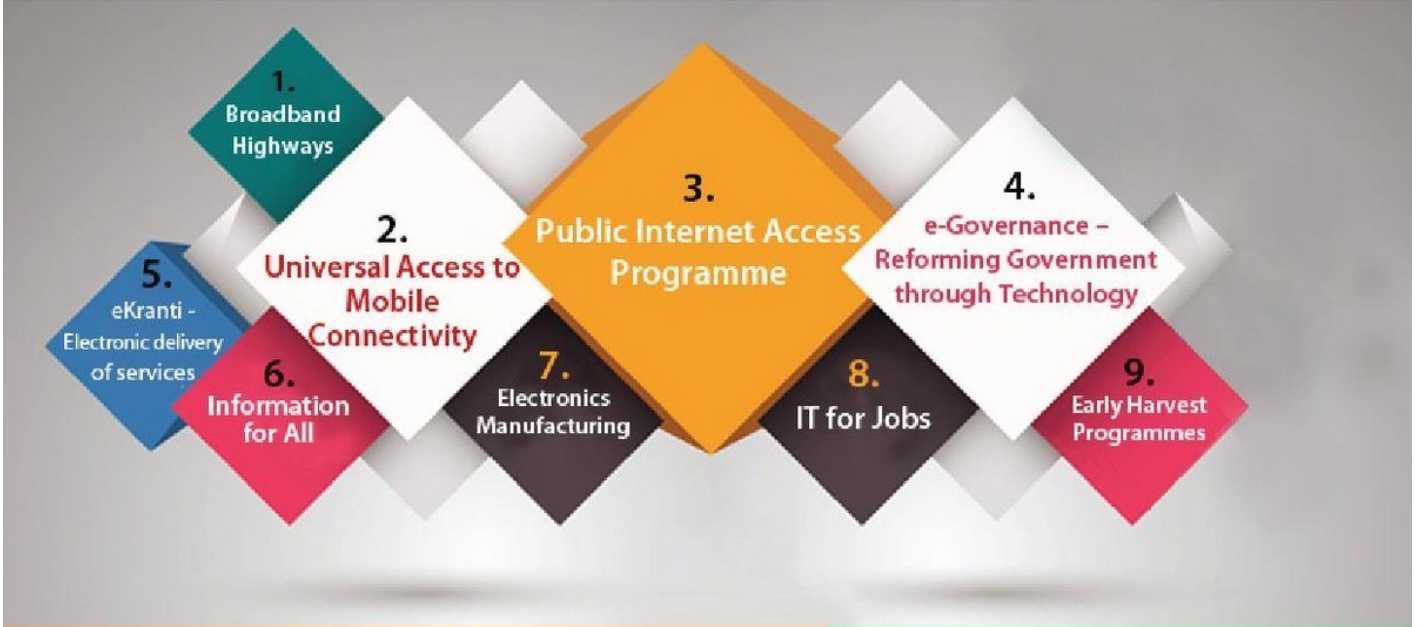
डजिटल इंडिया पहल के नौ स्तंभ:

- ब्रॉडबैंड हाईवे:** कनेक्टिविटी और डजिटल सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिये देश भर में व्यापक [हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क](#) के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना ।
- मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुँच:** दूरदराज़ के क्षेत्रों तक मोबाइल कवरेज का वसितार करना, जिससे सभी नागरिक मोबाइल सेवाओं से जुड़ सकें और डजिटल अर्थव्यवस्था में भाग ले सकें ।
- सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच कार्यक्रम:** वहीनीय इंटरनेट पहुँच उपलब्ध कराने, डजिटल विभाजन को दूर करने और डजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिये वंचित क्षेत्रों में [सामान्य सेवा केंद्र](#) स्थापित करना ।
- ई-गवर्नेंस, सरकारी सेवाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग:** नागरिक सहभागिता को बढ़ाते हुए पहुँच, दक्षता एवं पारदर्शता में सुधार करना ।
- ई-क्रांति: MyGov.in** जैसे प्लेटफॉर्म पहुँच एवं परिचालन दक्षता को प्राथमिकता देते हुए नागरिकों को सरकारी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी की सुविधा प्रदान करते हैं ।
- सभी के लिये सूचना:** ऑनलाइन पहुँच के लिये [सरकारी रिकॉर्ड को डजिटलाइज़](#) करना तथा [नवाचार एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु ओपन डेटा पहल](#) को बढ़ावा देना ।
- इलेक्ट्रॉनिकस वनरिमाण:** आयात को कम करने, रोज़गार सृजन करने तथा वनरिमाण क्लस्टरों के साथ-साथ [नविश प्रोत्साहनों](#) के

माध्यम से डिजिटल आर्थिक विकास को समर्थन देने हेतु स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक्स वनिर्माण को प्रोत्साहित करना ।

- नौकरियों के लिये सूचना प्रौद्योगिकी (IT): डिजिटल साक्षरता मशिन तथा स्कलि इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उद्योग जगत की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिये युवाओं के [आईटी कौशल](#) को बढ़ाना, [कौशल संवर्धन](#) के साथ-साथ आईटी क्षेत्र में रोजगार पर ध्यान केंद्रित करना ।
- अरली हार्वेस्ट अग्रीमेंट: तत्काल डिजिटल आवश्यकताओं को संबोधित करने वाली वशिष्ट परियोजनाओं को शामिल करना, जैसे-स्कूली प्रमाण-पत्रों तक ऑनलाइन पहुँच, [डिजिटल उपस्थिति एवं सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई](#) सुविधा ।

Nine Pillars of Digital India



//

डिजिटल इंडिया के लिये की गई वभिन्न डिजिटल इंडिया पहल क्या हैं?

- **आधार:** एक बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली जो नविसयियों को 12 अंकों की वशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करती है ।
- **भारतनेट:** यह परियोजना गाँवों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने तथा [ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएँ सक्षम बनाने के उद्देश्य](#) से बनाई गई है ।
- **स्टार्टअप इंडिया:** यह उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन, वतितपोषण तथा मार्गदर्शन के माध्यम से स्टार्टअप्स को समर्थन देने की एक पहल है ।
- **ई-नाम (e-NAM):** एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो कृषि बाजारों को जोड़ता है, उपज की कुशल बिक्री की सुविधा भी प्रदान करता है ।
- **डिजिटल लॉकर:** महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने के साथ-साथ डिजिटल रूप से उन तक पहुँचने के लिये एक क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म ।
- **भीम यूपीआई:** एक डिजिटल भुगतान प्रणाली जो स्मार्टफोन का उपयोग करके सुरक्षित [पीयर-टू-पीयर लेन-देन को सक्षम](#) बनाती है ।
- **ई-साइन फ्रेमवर्क:** डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके दस्तावेजों पर ऑनलाइन हस्ताक्षर करने की अनुमति प्रदान करता है ।
- **MyGov:** एक नागरिक सहभागिता मंच जो शासन एवं नीतितगत चर्चाओं में भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है ।
- **ई-हॉस्पिटल:** ऑनलाइन पंजीकरण और स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुँच सहित डिजिटल अस्पताल सेवाएँ ।
- **SWAYAM प्लस प्लेटफॉर्म**
- **उमंग एप (UMANG App)**
- **समार्ट सर्टि**
- **डिजिटल इंडिया अधिनियम (DIA), 2023:** प्रस्तावित अधिनियम का उद्देश्य भारत के बढ़ते इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार, तकनीकी प्रगति और नई डिजिटल चुनौतियों के अनुकूल, पुराने [सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000](#) को प्रतिस्थापित करना है । DIA, AI और ब्लॉकचेन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को ज़िम्मेदारी से अपनाने के लिये दशा-नरिदेश प्रदान करता है, नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए नवाचार को प्रोत्साहित करता है ।

डजिटल इंडिया के संबंध में चुनौतियाँ और आगे की राह क्या है?

चुनौतियाँ	आगे की राह
<ul style="list-style-type: none"> • डजिटल डिविड: 2021 तक भारत की इंटरनेट पहुँच दर लगभग 47% थी, जिससे आधी से ज़्यादा आबादी बिना पहुँच के रह गई। ग्रामीण क्षेत्र विशेष रूप से पछिड़े हुए हैं, जहाँ शहरी क्षेत्रों में 67% की तुलना में केवल 32% ग्रामीण इंटरनेट पहुँच है। • यद्यपि भारतनेट ने प्रगति की है, फरि भी वर्ष 2021 तक 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से केवल 1.7 लाख ही ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थीं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के अंतराल को दर्शाता है। 	<ul style="list-style-type: none"> • डजिटल विभाजन को कम करना: सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क स्थापित करने के लिये पीएम-वाणी योजना जैसी पहलों को लागू करना, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक 2 मिलियन हॉटस्पॉट स्थापित करना है। • 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना, जिसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक 40% आबादी को कवर करना है।
<ul style="list-style-type: none"> • डजिटल साक्षरता: डजिटल साक्षरता की कमी एक बाधा बनी हुई है। IAMAI यानी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड कंता की वर्ष 2021 की रिपोर्ट से पता चला है कि भारत की केवल 34% आबादी ही डजिटल रूप से साक्षर मानी जाती है। 	<ul style="list-style-type: none"> • डजिटल साक्षरता बढ़ाना: वर्ष 2023 तक 60 मिलियन ग्रामीण परिवारों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य तक पहुँचने के लिये प्रधानमंत्री ग्रामीण डजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) का वसितार करना। • स्कूल पाठ्यक्रम में डजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को शामिल करना, जिसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक डजिटल रूप से साक्षर जनसंख्या को 34% से बढ़ाकर 50% करना है।
<ul style="list-style-type: none"> • साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएँ: CERT-In के अनुसार भारत को वर्ष 2020 में 11 मिलियन से अधिक साइबर सुरक्षा घटनाओं का सामना करना पड़ा। • भारत डजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDPA) एक ऐतिहासिक कानून है जिसका उद्देश्य डजिटल युग में व्यक्तियों की नजिता की रक्षा करना है। 	<ul style="list-style-type: none"> • साइबर सुरक्षा का सुदृढीकरण: लक्ष्य मजबूत कानून और नजिता हेतु सुदृढ तंत्र के माध्यम से वर्ष 2026 तक साइबर अपराध की घटनाओं को 50% कम करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।
<ul style="list-style-type: none"> • ई-गवर्नेंस चुनौतियाँ: यद्यपि ई-गवर्नेंस पहल में सुधार हुआ है फरि भी दूरवर्ती क्षेत्रों में डजिटल पहचान सत्यापन और सेवा के वतिरण संबंधी समस्याएँ बनी हुई हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> • ई-गवर्नेंस की दक्षता वृद्धि: वर्ष 2024 तक सभी सरकारी सेवाओं के लिये एकीकृत डजिटल पहचान प्रणाली क्रियान्वित की जानी चाहिये। वर्ष 2025 तक उमंग ऐप की सहायता से उपलब्ध सेवाओं की मौजूदा संख्या 1,251 से बढ़ाकर 2,500 की जानी चाहिये।
<ul style="list-style-type: none"> • कौशल अंतराल: नैसकॉम फ्यूचरस्किल्स रिपोर्ट के अनुसार भारत के 20% तकनीकी पेशेवरों में भविष्य की नौकरियों के लिये आवश्यक प्रासंगिक डजिटल कौशल का अभाव है। 	<ul style="list-style-type: none"> • कौशल अंतराल को पाटना: उभरती प्रौद्योगिकियों में पेशेवरों को कुशल बनाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय डजिटल कौशल कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। एक नजिी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2026 तक 30 मिलियन डजिटल रूप से कुशल पेशेवरों की आवश्यकता होगी।

दृष्टांमिन्स प्रश्न:

प्रश्न: डजिटल इंडिया पहलों का नरीक्षण करते हुए उनके समक्ष वदियमान चुनौतियों और इन चुनौतियों के प्रभावी समाधान के लिये आवश्यक उपायों का उल्लेख कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के

2022

प्रश्न: नमिनलखिति पर वचिार कीजिये: (2022)

1. आरोग्य सेतु
2. कोवनि
3. डजिीलॉकर
4. दीकषा

उपर्युक्त में से कौन-से ओपन-सोर्स डजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं?

(a) केवल 1 और 2

- (b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/nine-years-of-digital-india-initiative>

